आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 22.03.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला–2027 और प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
- केंद्र सरकार ने राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्त्रां, होटल, कैंटीन, ढाबों तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी।
- अल्मोड़ा में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

.....

संबोधन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है। इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल हैं। नैनीताल स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के स्थापना दिवस को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने यह बात कही।

.....

वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला–2027 और प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके तहत हरिद्वार में प्रस्तावित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर–2 भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पहली किश्त के रूप में 20 करोड़ 11 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।

उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में कम्यूनिटी हॉल निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पहले चरण में 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण, मेला स्थल निर्माण और आंतरिक मार्गों के निर्माण से जुड़े कई कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

आपदा न्यूनीकरण के तहत चम्पावत में शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 11 करोड़ 59 लाख रुपये की योजना के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 4 करोड़ 64 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके

अलावा रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ 74 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें पहले चरण में 5 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न नगर निकायों में पार्क निर्माण, सौंदर्यीकरण और ओपन जिम स्थापना के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा शहरी विकास विभाग के तहत अवस्थापना विकास निधि से 13 योजनाओं के लिए 53 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं देहरादून में बौद्ध विकास योजना के अंतर्गत तीन परियोजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति के सापेक्ष दूसरे चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

.....

शिक्षा पुनःर्जीवन

देहरादून में नवरात्र के अवसर पर जिला प्रशासन ने जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करने की पहल को आगे बढ़ाया है। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 10 बालिकाओं की शिक्षा फिर से शुरू कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की।

जिला प्रशासन के 'नंदा–सुनंदा' प्रोजेक्ट के तहत अब तक ज़िले की 136 से अधिक जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की बेटियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी शिक्षा आर्थिक या पारिवारिक कारणों से बीच में रुक गई थी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि बालिकाओं को शिक्षित कर उनके भविष्य को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

.....

एलपीजी अतिरिक्त आवंटन मंजूरी

केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10 प्रतिशत आवंटन भी शामिल है। यह अतिरिक्त आवंटन राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि यह आवंटन सोमवार से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को कुल 50 प्रतिशत आवंटन से वाणिज्यिक एलपीजी प्राप्त करने के लिए पात्र होने से पहले तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा।

.....

प्रशिक्षण

अल्मोड़ा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में "संस्थाएं एवं समावेशन" विषय पर द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रशिक्षण में हवालबाग, लमगड़ा, धौलादेवी, भैसियाछाना और द्वाराहाट के स्वायत्त सहकारिता समूहों के प्रतिनिधियों के साथ ही ब्लॉक स्तर पर परियोजना से जुड़े कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनरों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका संवर्धन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने भी आय बढ़ाने से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

जिला परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी ने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने और स्वायत्त सहकारिता समूहों को मजबूत बनाना है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें।

प्रशिक्षण में भाग ले रही शगुन ने बताया कि ट्रेनिंग के माध्यम से समूहों को आय संवर्धन और ग्रामोत्थान से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई है।

.....

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने को बनेगी एसओपी। इस शीर्षक से दैनिक जागरण समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार तेज रफ्तार वाहन दुर्घटना का बड़ा कारण है इसे देखते हुए इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जायेगी।

नीति घाटी में होगी 75 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन, पंजीकरण शुरू, अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है– चीन सीमा क्षेत्र में 31 मई और एक जून को नीति घाटी में पर्यटन विभाग 75 और 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ करवायेगा।

राज्य के सभी जिलों में विकसित किए जाएंगे मॉडल सोलर विलेज। नवोदय टाइम्स में इस शीर्षक से छपी खबर के अनुसार ऊर्जा विभाग व उरेडा की ओर से हर जिले के एक गांव को किया जाएगा विकसित। चयनित गांव को दी जाएगी एक करोड रुपए की आर्थिक सहायता।

.....